आधार की विश्वसनीयता गम्भीर रूप से घट जाएगी; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के ऐसे छात्रों में अनुमानतः वृद्धि दर कितनी होगी जिनके इस वर्ष क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने की संभावना है और गत 5 वर्षों में यह दर क्या थी ;

(ग) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली में बैठकर देश भर की शिक्षा प्रक्रिया पर नियंत्रण नहीं कर सकता; यदि हां, तो क्या सरकार इसके कार्यक्षेत्र को कम करने का विचार कर रही है ; और

(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षित उन छात्रों का पिछले 3 वर्षों के लिए औसत दर क्या है जिन्हें देश में रोजगार मिल गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही): (क) जी, हां । आई० आई० टी० मद्रास के निदेशक, प्रो० एल० एस० श्रीनाथ ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि फिलहाल परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित नही की जाती हैं ।

(ग) आई० आई० टी० विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं ।

(घ) औसत दर लगभग 80 प्रतिशत है ।

Attack on Soviet Trade Delegation at Calcutta

2006. SHRI KAPIL VERMA :
SHRIMATI VEENA VERMA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a Soviet trade delegation was attacked by some jute mill workers in Calcutta on April 23, 1989, if so, what are the details of the incident;

(b) whether the Soviet Embassy has taken up the i matter with the Government of" India or with the West Bengal Government ; and

(c) whether the M/o External Affairs have made any enquiries on their own on the subject, of so, what is the outcome thereof ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Merit-Based Promotions of Teachers in Kendriya Vidya lays

2007. SHRI MOSTAFA BIN QUASEM :
SHRI ASHOK NATH VERMA :
DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY :
SHRI CHATURANAN MISHRA :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that promotions to the posts of Vice-Principal, Headmaster and Principal etc., are given on seniority-cum-merit basis in Kendriya Vidyalaya Sangathan ;

(b) if so, what are the indices of merit and how it is measured

(c) whether any representations had been received in this regard; and

(d) if so, what is the reacti of the Sangathan thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI) : (a) Yes, Sir.

(b) Kendriya Vidyalaya Sangathan follows the method prescribed by the Government of India in the DPAR OM No. 22011/3/76-Estt.(D) dated 24.12.80 and 22011/6/75-Estt.(D) dated 30.12.76. This prescribes that the officers in the field of selection, excluding those considered unfit for promotion by the Departmental Promotion Committee, should be classified by the DPC as "outstanding", "very good", and "good" on the basis of their merit, as assessed by the DPC after examination of their respective records of service. It is entirely left to the DPC to make its own classification o f the officers being considered by them for promotion to selection posts, irrespective of the grading that may be shown in the CRs. The panels should, thereafter be drawn up to the extent necessary by placing the names of the "outstanding" officers first, followed by the officers categorised as "very good" and followed by the officers categorised as "good". The inter-seniority of officers belonging *to* any one category would be the same as their seniority in the lower grade.

(c) and (d) Representations have been received mostly from those superseded by their juniors which is inherent in the method of selection.

सड़कों के सुधार से होने वाली बचत

2008. श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स एण्ड कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा करवाये गये अध्ययन के इस निष्कर्ष की जानकारी है कि अच्छी सड़कों से ही सड़क परिवहन पर होने वाले खर्च में 15 प्रतिशत की कमी की जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन की जांच की है, और यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के किस सीमा तक स्वीकार किये जाने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो यह बचत करने के लिए देश की सड़कों में किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है ;

(घ) क्या सरकार सड़कों के रख-रखाव की पद्धति में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार को इस संबंध में इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा किए गए किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं होता ।